एक वास्तविक सुधार

लेखक- एमएस साहू (चेयरपर्सन, इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

14 मार्च, 2020

"दिवाला संहिता की उपलब्धि यह है कि देनदार अब प्रारंभिक चरण में ही डिफॉल्ट का समाधान कर लेते हैं।"

आमतौर पर पुरानी व्यवस्था के लाभार्थी (बैंक) हर सुधार को अग्नि परीक्षा के कई दौर से गुजारा करते थे। वे सुधार के खिलाफ जनता की राय का निर्माण करते थे, जिसे हर संभव मंच पर चुनौती देते थे, कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते थे, तथ्यों और आँकड़ों को गलत तरीके से पेश करते थे और यहाँ तक कि अफवाहें और बेबुनियादी खबरें भी फैलाते थे। हालाँकि, इस तरह के विरोध अंततः सुधार को काफी बेहतर और मजबूत बना देते थे। दिवाला सुधार (IBC) भी इसी प्रक्रिया का एक अहम् हिस्सा है। इसे पहले ही दिन से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था। इसके कार्यान्वयन के साथ विरोध में भी वृद्धि हुई, क्योंकि डिफॉल्टरों ने धीरे-धीरे अपनी स्वतंत्रता खो दी और कंपनियों ने भी इनसे मुँह फेर लिया। IBC ने अपने वादे को पूरा करते हुए वैश्विक मान्यता अर्जित की और डिफॉल्ट के मामले में हितधारकों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गया।

हालाँकि, IBC परिणामों के आसपास कुछ मिथकों को खतम करने की आवश्यकता है। मैं (लेखक) गणनाओं को सरल रखने के लिए आँकड़ों का उपयोग करके समझाने की कोशिश करूँगा। ज्यादातर मिथक रिकवरी यानी वसूली के आस-पास व्याप्त हैं। इसे हम एक उदहारण से समझने की कोशिश करते है। Synergies Dooray, IBC के तहत हल होने वाली पहली कंपनी थी। यह एक दशक से अधिक समय तक औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के साथ जुड़ा रहा। इसकी संपत्ति का वास्तविक मूल्य 9 करोड़ रुपये था, जब इसने IBC प्रक्रिया में प्रवेश किया। हालाँकि, इसने लेनदारों को 900 करोड़ रुपये दिए थे। संकल्प योजना (resolution plan) से 54 करोड़ रुपये की आय हुई। कुछ ने IBC की निंदा की क्योंकि संकल्प योजना ने लेनदारों के दावों का मात्र 6 प्रतिशत हिस्सा हासिल किया, इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि वह कंपनी से 600 प्रतिशत वसूल कर सकता था, जो एक दशक से अधिक समय से खराब हालत में थी। यदि कंपनी के शेयरों को विनिवेश कर दिया जाता, तो लेनदारों को उनके दावों का 9 करोड़ रुपये मिल जाता, जो उनके दावों का एक प्रतिशत था।

आइए इस मिथक की जाँच करें कि संकल्प योजनाओं के माध्यम से वसूली निराशाजनक है। दिसंबर 2019 तक संकल्प योजनाओं के माध्यम से दो सौ कंपनियों को बचाया गया था। उनके पास लेनदारों का 4 लाख करोड़ रुपये बकाया है। हालाँकि, उनके पास उपलब्ध संपत्ति का वास्तविक मूल्य, जब वे IBC प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, केवल 0.8 लाख करोड़ रुपये था। IBC मौजूदा परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ाता है, न कि उन परिसंपत्तियों को जो मौजूद नहीं हैं। IBC के तहत लेनदारों ने 1.6 लाख करोड़ रुपये की वसूली की, जो इन कंपनियों के वास्तविक मूल्य का लगभग 200 प्रतिशत था।

आईबीसी के तहत रिकवरी आकस्मिक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य संकट में कंपनियों को बचाना है। एक हालाँकि, एक मिथक यह भी है कि IBC प्रक्रिया ने 200 कंपनियों को बचाया है, लेकिन इसने 800 कंपनियों को लिक्विडेशन के लिए भेजा था। लिक्विडेशन में आने वाली कंपनियों की संख्या बचाए गये कंपनियों की तुलना में चार गुना है। बचाई गई

कंपनियों में 0.8 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति थी, जबकि लिक्विडेशन के लिए संदर्भित कंपनियों के पास आईबीसी प्रक्रिया में प्रवेश करने पर संपत्ति 0.2 लाख करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, मूल्य के संदर्भ में, जिन परिसंपत्तियों को बचाया गया है, वे लिक्विडेशन के लिए भेजे गए परिसंपत्तियों की तुलना में चार गुना हैं। यहाँ ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि बचाई गई कंपनियों में से एक तिहाई या तो मृत थीं या बीआईएफआर (BIFR) के तहत थीं और जिन कंपनियों को लिक्विडेशन के लिए भेजा गया था उसमें तीन-चौथाई या तो मृत थीं या बीआईएफआर के तहत थीं।

अगला मिथक यह है कि आईबीसी परिसमापन के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार का नुकसान करता है। यहाँ गलत तरीके से व्याख्या की गयी है कि 600 कंपनियों (जिनके लिए डेटा उपलब्ध हैं और जो लिक्विडेशन के लिए आगे बढ़ी हैं) के पास संपत्ति कम से कम लेनदारों के कुल दावे (4.6 लाख करोड़ रुपये) के बराबर है। दुर्भाग्य से, उनके पास संपत्ति केवल 0.2 लाख करोड़ रुपये है। इसे मिनरल्स लिमिटेड और ऑर्किड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। इन पर 8,163 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि उनके पास बिल्कुल संपत्ति और रोजगार नहीं था। इस संदर्भ यह महत्त्वपूर्ण है कि एक कंपनी के पास कितनी संपत्ति है या वह रोजगार प्रदान करता है या नहीं, न उस इस पर कितना बकाया है। IBC प्रक्रिया 0.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य की बेकार या कम-उपयोग की गई संपत्तियों को जारी करेगी, जो व्यापार और रोजगार के लिए समय के साथ भंग हो गई होगी। 93 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने वाली पचास कंपनियों को पूरी तरह से लिक्विडेट कर दिया गया है।

तनावग्रस्त संपत्ति का एक जीवन चक्र होता है, इसका मूल्य समय के साथ कम हो जाता है, अगर संकट को संबोधित नहीं किया जाता है। तनावग्रस्त संपत्ति के जीवन चक्र के शुरुआती चरणों में हजारों देनदार डिफॉल्ट का निपटारा कर रहे हैं। ये चरण बीमारी की रोकथाम के लिए निवारक देखभाल, प्राथमिक देखभाल, माध्यमिक देखभाल और तृतीयक देखभाल के समान हैं। केवल कुछ कंपनियां, जो इनमें से किसी भी चरण में संकट को संबोधित करने में विफल रहती हैं, लिक्विडेशन चरण तक पहुँचती हैं। इस स्तर पर, कंपनी का मूल्य काफी हद तक समाप्त हो जाता है।

व्यवसाय को समझने वाले और परिष्कृत पेशेवरों के समर्थन करने वाले हितधारक सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद खुली आँखों से IBC का उपयोग कर रहे हैं। उनके व्यावसायिक ज्ञान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। IBC के तहत अब तक दायर 25,000 आवेदन यह दर्शाते हैं कि हितधारकों को इस कानून पर विस्वास है।

GS World Committed To Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) चर्चा में बना हुआ है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. इसका मुख्य काम समयबद्ध तरीके से कंपनी को पुनर्जीवित करना है।
2. इसके माध्यम से सभी वर्गों के देनदारों और लेनदारों को एक सामान्य मंच प्रदान किया जाता है।
3. इसके द्वारा किसी कंपनी के हितधारकों सहित लेनदारों के हितों की रक्षा भी की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3

(c) 2 और 3 (d) उपरोक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Recently, the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has been in the news. Consider the following statements in this context:

1. Its main job is to revive the company in a time bound manner.
2. Through this a common platform is provided to the debtors and creditors of all classes.
3. It also protects the interests of the creditors including the stakeholders of a company.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 1 and 3

(c) 2 and 3 (d) All of the above

नोट : 13 मार्च को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. "दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC) भारतीय आर्थिक शासन व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिसने दबावग्रस्त संपत्तियों के तार्किक निपटान में सफलता पाई है।" इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

(250 शब्द)

"The Insolvency Bancrupty Code (IBC) is a major step in the Indian economic governance system that has succeeded in the rational disposal of stressed assets." Analyze this statement.

(250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।